2630

RAJYA SABHA

Oral Answers

Wednesday, the 23rd September, 1964/ the 1st Asvina, 1886 (Saka)

The House met at eleven of the dock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरकों के मुल्य

*३४३. श्री भगवत नारायण भागव : क्या योजना मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाइट्राजनो तथा फास्फेडी उर्वरकों के मूल्य कम करने के सम्बन्ध में याजना ग्रायांग के विशेषज्ञ दल ने क्या राय दो ; ग्रीर

(ख) इस दल को सिफारिशों के प्रति सरकार की क्या प्रतिकिंग है ?

t [PRICES OF FERTILIZERS

•353. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the opinion given by the Panel of Experts of the Planning Commission in regard to reduction in the prices of nitrogenous and phosphatic fertilizers; and

(b) what is Government's reaction to the recommendations of the Panel?]

t[THE MINISTER OF PLANNING (SHRI B. R. BHAGAT): (a) The existing prices of

योजना मंत्री (श्री बी० ग्रार० भगत) : उर्वरकों की वर्तनान की तर्ते बहुत ज्यादा हैं । यद्यपि उर्वरकों की कुछ किस्मों को कोमतें कुछ समय पहले घटाई गई हैं फिर भी, यदि जरूरत पड़े तो सहायता देकर उन्हें घटाने की ग्रावश्यकता है ।

(ख) यह विचाराधीन है। fertilisers are too high

t [] English translation. 717 RSD—1 and though some reductions have lately been made in the case of certain types of fertilisers, there is need to reduce them further, if necessary, by subsidising them.

(b) It is under consideration.]

SHRI JOSEPH MATHEN: Is it a fact that an

श्वी भगवत नारायण भागंव ः क्या मंत्री महोदय यह बताने की ऊपा करेंगे कि प्लानिंग कमिशन के पैनल आफ एवसनर्ट्स ने जिस रेट का संकेत दिया था उसमें और आज कल के रेट्स में कितना अन्तर है ?

श्वी बी॰ झार॰ भगतः : प्लानिग कमिशन ने तो नहीं लेकिन वॉकंग जुप ने जिसने फटिलाइजर्स पर और एप्रिकल्चर के सिलसिले में अभी विचार किया है उसने कहा है कि फटिलाइजर्स की खपत ज्यादा बढ़ और किसानों को यह स्वीकृत हो इसलिये इसके दाम में जो अभी है उससे कम से कम २० परसेंट कमी होनी चाहिए । तो यह मैंने कहा कि यह विचाराधीन है ।

श्री भगवत नारायण भागंव : क्या गवर्नमेंट का घ्यान इत ग्रार ग्राकर्षित हुआ है कि जो छोटे-छोटे किसान हैं वे फटिनाइजर्स खरीदने में बिल्कुल ग्रसमर्थ हैं तो क्या गवर्नमेंट यह विचार करेगी कि छ टे-छोटे किसानों को बिना मल्य के फटिनाइजर्स दिया जा सके?

श्री बीo झार० भगत : बिना मूल्य के दिया जाना ता बहुत कठित है, आ बिर उसकी पूरो कीमत सरकार को देनो पड़ेगी और उसमे बहुत रुग्या लगेगा मगर यह पूरी के शिश ह गो जै ता कि मैंने कहा कि ग्रगले वर्ष में जहां तक संभव हो इसके दाम घटाये जाने चाहिए और उनका फटिनाइ ब्रसं खरोद सकें इसके लिए कर्जे की व्यवस्था सस्ते सूद पर हो को आपरेटिव या दूसरे जरियों द्वारा---ता यह सब इन्त बाम होगा !

American expert team visited this country and it suggested ways and means to supply cheaper fertilisers to agriculturists in this country?

SHRI B. R. BHAGAT:: Sir, the fertiliser production takes into account all the technological and economic advances that have recently been achieved and if the units are set up on that basis, it is possible to reduce considerably the prices of fertilisers.

SHRI C. D. PANDE: Sir, there is a retention charge of Rs. 50 per ton and also a charge of Rs. 50 as distributors' commission. That makes Rs. 100 a ton which is a very substantial portion of the price charged from the consumers. Will the Government do away at 'east with this so that there should be no profit and also will the Government see to it that the distribution charge also is reduced to a reasonable limit?

SHRI B. R. BHAGAT: Sir, the charges that go to the intermediaries are not to that extent but efforts are made to reduce them to the extent possible.

श्वी विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान् को ज्ञात है कि शासन ढारा मूल्यों में कुछ सः ग्यता देने के बावजूद भी कई सहकारी समितियां व्यवस्था के ज्ञान के ग्रभाव में, व्यापारिक ज्ञान के ग्रभाव में, डेमरेज म्रोर ग्रन्थ मदों पर इतना ग्रधिक खर्चा कर देती हैं कि हमारी दी हुई सुविधाय्रों के बावजूद भी उनका खर्चा ग्रधिक होने के कारण कीमत व्यधिक होती है । तो ऐसी दशा में उस खर्चे में कमी लाने के लिए क्या शासन क्रूछ करेगा?

श्री बी० श्रार० भगतः इन सब वातों पर विचार हुश्रा है और गठरो छानबीन भी हुई है। ये सब प्रशासन की गड़वड़ियां हैं जिसकी बजह से देरी हो जाने से या डेमरेज चार्ज लगने से जो कास्ट बढ़ता है तो जठां तक यह कम हो सके इसकी कोशिश की जा रही है श्रीर इसके लिये सुझाव भी दिये गये हैं।

SHRI SANTOKH SINGH: In spite of the fact that cheap labour is available in India and also the raw materials are indigenously available, may I know why the cost of manufacture of these fertilisers, nitrogenous or phos-phatic, is high in India? Is it because of the fact that the capital structure goes high because of the costly imported plants?

SHRI B. R. BHAGAT: Well, this is a matter of detail and all these questions will be looked into. When the new fertiliser plants come into existence, efforts will be made to take advantage of the technological and economic advances that have been made.

श्वी देवी सिंह : यह सरकार जो इंटर-मीडियरीज इसमें रख रही है इसके बजाय सीधे काश्तकार को क्यों नहीं दे जब कि हमारी सरकार के पास पटवारी वगैरह की मशीनरी मौजूद है ? तो इसको प्राइवेट तरीके पर क्यों दिया जाता है, इसको सरकार क्यों नहीं देती ?

श्री बी० श्रार० भगतः जो बांटने की व्यवस्था है वह ज्यादातर कोश्रापरेटिव्ज के जरिये है । जहां कोग्रापरेटिव कमजोर है वहां सीधे देने की बात हो रही है । जहां कोग्रापरेटिव मजबूत है वहां काम ठीक से चलता है ग्रीर वहां इसके बांटने की ठीक व्यवस्था चलती है, जहां नहीं है वहां गड़बड़ चलती है । तो यह तो ह्युमन ग्रार्गेनाइजेशन को कुशल करने की बात है ग्रौर उसको ग्रच्छा बनाने पर ही यह हो सकता है ।

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Sir, I would like to know how the prevailing prices in India compare with the prices obtaining in important countries like Japan, the United States of America and the U.K. If the ruling prices are far below the prices in India, how is it that in India the prices are much higher than the prices that are prevailing in those countries?

SHRI B. R. BHAGAT: Sir, our fertiliser prices—in India—are higher than the prices in every other country except Spain.

2634

श्वो देवकीनंदन नारायणः क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फटिलाइजर्स में काफी एडल्ट्रेशन होता है तो उसे रोकने के लिए सरकार की ग्रोर से क्या कोश्विश की जा रही है ?

श्री बो० ग्रार० भगतः उसकी भी रोक्याम करने की कोशिश की जा रही है।

खाली सरकारी इमारतें

*३४४. श्री विमलकुनार मन्नालालजी चौरड़ियाः क्या निर्माण, तथा क्रावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 9 अप्रैल, 9९६४ को दिल्ली के किस-किस क्षेत्र में कितनी कितनी सरकारी इमारतें खाली पड़ी हुई थीं; और है

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित इमारतें कब से खाली पड़ी हैं और इसके क्या क्या कारण हैं ?

t [VACANT GOVERNMENT BUILDINGS

•354. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) the areas in Delhi where Government buildings were lying vacant on 1st April, 1964 and the number of such buildings in each of these areas; and

(b) since when the buildings mentioned in part (a) above are lying vacant and what are the reasons therefor?]

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहर चन्व सन्ना) : (क) पहली प्रप्रैल, ११६४ को दिल्ली में तकरीवन कुल ३४,६०० सरकारी इमारतों में ते नीचे लिखी गयी महज २२३ इमारतें मुखतलिफ इलाकों में खाली पड़ी थीं ।

(ख) ये क्वार्टर मुखतलिफ तारीखों से खाली पड़े हैं। इनमें से मिन्टो रोड ग्रौर डो॰ ग्राई॰ जैंड॰ एरिया के ज्यादातर क्वार्टर इसलिए खाली पड़े हैं क्योंकि वे खतरनाक करार दिये जा चुके हैं। दूसरे एरिया में क्वार्टर, मरम्मत, एक मंजिल से दो मंजिल में तबदील करने, छतों को बदलने ग्रौर फ़र्गों को बदलने वगैरा की वजह से खाली हैं।

t[THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI MEHR CHAND KHANNA); (a) Out of a total of about 35,600 Government buildings in Delhi, only about 223 buildings were lying vacant in different areas on the 1st April 1964.

(b) These quarters are vacant from different dates. Most of the quarters in the Minto Road and the D.I.Z. area* are vacant as they have been declared dangerous and unfit for occupation. Quarters in other areas have been lying vacant for carrying out repairs, conversion of single storey buildings into double storey, re-roofing and re-ftooring etc.]

श्वी विमलकुमार मन्नालालजी बौरड़ियाः क्या श्रीमान यह बतलायेंगे कि विमाग ने कोई ऐसी योजना बनाई है ग्रयवा नही---नया निर्माण जो चल रहा है सो चल ही रहा है---कि जा पुराने मकान हैं ग्रीर जो दुरुस्ती के काबिल हैं, जैसे कि फर्श वगैरह को ठीक करा कर काम में ग्रा सकते हैं, उनके लिए प्रापरिटी बेसिस पर कुछ तय करके उनको ठीक करायें ताकि लोगों को उनमें बसाने की व्यवस्था की जा सके? तो क्या इसको ग्राप प्रायरिटी निश्चित करके करायेंगे ?

t [] English translation.